(ग) जी, हां ।

(घ) इन दोनों कारखानों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन बनाये रखने/बढ़ाने के लिए किये गये मुख्य-मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) कोयले की देशीय सप्लाई में वृद्धि करने के लिए राख की कम मात्रा वाले कोककर कोयले का आयात किया जा रहा है । इसके साथ-साथ कोयले के देशीय उत्पादन में भी वृद्धि की जा रही है । ;

(2) कारखानों की अपनी वर्तमान विद्युत उत्पादन इकाइयों में बिजली का अधिकाधिक उत्पादन किया जा रहा है और सार्वजनिक स्रोतों से मिलने वाली बिजली के उत्पादन में भी वृद्धि की जा रही है ;

(3) बिजली की उपलब्धि के अनुसार जमा स्टाक से पिन्डों/सिल्लियों का अधिक बेलन किया जा रहा है ;

(4) कोयला तथा बिजली सप्लाई करने वाले अभिकरणों और रेलवे के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है ;

(5) कारखानों को सही हालत में रखने के लिए निवारक-रख-रखाव तथा पूंजीगत मरम्मतों के लिए योजनायें बनाना और उनको कार्यान्वित करना; और

(6) कारखानों की अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए व्यवस्था करना ।

Finances given to Dalmia Group of companies

2550. SWAMI INDERVESH :
SHRI RAM VILAS PASWAN :
SHRI RAJESH KUMAR SINGH :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the financial institutions which have financed Dalmia Group of Companies during the last five years, year-wise.

(b) what are the names of Dalmia concerns which have been financed ; and

(c) what is the total amount financed ; and the terms on which the companies were financed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) to (c). For purposes of classifying companies as belonging to Houses or Groups, financial institutions use a list of undertakings registered under the MRTP Act, which does not contain a group called Dalmia Group.

However, information on financial assistance extended by the term lending financial institutions to concerns owned by the Dalmias is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the House.

Separate organisation for dealing with Indian Companies raising capital in foreign Money Markets

2551. SHRI B. V. DESAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a separate Centralized organisation has been proposed to deal with Indian Companies raising capital directly in foreign money markets ;